भारतीय जनता पार्टी

(केन्द्रीय कार्यालय)
11, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001
फोन नं. : 23005700; **फैक्स :** 23005787

दिनांक : 29 जनवरी 2013

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दिया गया प्रेस वक्तव्य

डीजल के लिए दोहरी मूल्य व्यवस्था

भाजपा डीजल के लिए लागू की गई दोहरी मूल्य व्यवस्था के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की आलोचना करती है जिसने आम आदमी पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यह छद्म मूल्य वृद्धि है। सरकार ने डीजल को नियंत्रण मुक्त करके उपभोक्ताओं की दो श्रेणियां बना दीं, यानि थोक में इस्तेमाल करने वाले और ऐसे उपभोक्ता जो तेल कंपनियों के रिटेल आउटलेट से डीजल खरीद रहे हैं। एक तरफ रिटेल आउटलेट से खरीदारी करने वाले उपभोक्ताओं को 50 रुपये से 54 रुपये प्रति लीटर के मूल्य पर डीजल खरीदना पड़ रहा है जबकि थोक इस्तेमालकर्ताओं को 62 रुपये से लेकर 65 रुपये प्रति लीटर देने पड़ रहे हैं।

इस फैसले के कारण राज्य परिवहन को 3000 करोड़ रुपये अधिक देने पड़ेंगे। इसी तरह रेलवे को 3000 करोड़ रुपये अधिक का बोझ उठाना पड़ेगा। जनोपयोगी सेवाओं जैसे शहरों में चलने वाली बसों और सार्वजनिक उपयोग की अन्य सेवाओं को 3000 करोड़ रुपये अधिक देने पड़ेंगे। निजी उद्योगों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को हर वर्ष 6000 करोड़ रुपये अधिक देने होंगे। इसका मतलब है कि सरकार ने नई श्रेणी जिसे ''थोक खरीदार'' कहा जा रहा है, के जरिये एक ही झटके में करीब 18,000 करोड़ रुपये का बोझ डाल दिया है।

जाहिर है कि ये सभी सेवाएं आम आदमी पर बोझ डालेंगी, जो डीजल के मूल्यों में मासिक बढ़ोतरी के कारण पहले से ही परेशान है। सरकार द्वारा डीजल से नियंत्रण हटाने के कारण इस क्षेत्र पर करीब 60,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

यहां तक कि मछुआरों को भी थोक उपभोक्ता घोषित किया जा चुका है। उपभोक्ताओं को डीजल देने के नये नियमों के साथ, किसानों तक को थोक डीजल का मूल्य देने पर मजबूर होना पड़ा है।

भाजपा मांग करती है कि दोहरी मूल्य व्यवस्था और डीजल के खुदरा मूल्यों में बार–बार की जाने वाली मासिक बढ़ोतरी को तत्काल वापस लिया जाए।

तेलंगाना मुद्दा

भारतीय जनता पार्टी अलग तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे को बार–बार टालने की यूपीए सरकार की चाल की निंदा करती है। सरकार तेलंगाना के गठन के बारे में 28 जनवरी 2013 तक अंतिम फैसला करने के अपने नवीनतम वादे से मुकर गई है। इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक के बाद दिसम्बर के महीने में केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने इसका वादा किया था। यह तेलंगाना की जनता के साथ एक और विश्वासघात है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता।

9 दिसम्बर 2009 को तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने घोषणा की थी कि पृथक तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति के कारण यह उसी दिन रुक गई। इतिहास में जाएं तो कांग्रेस ने 1980 में श्री चेन्ना रेड्डी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन के दिनों से ही तेलंगाना की जनता के साथ धोखा किया है।

भाजपा लगातार तेलंगाना राज्य के गठन की मांग करती रही है। आज हम एक बार फिर मांग करते हैं कि केन्द्र सरकार तुरन्त नये राज्य के गठन की तत्काल घोषणा करे और बजट सत्र के पहले सप्ताह में आवश्यक विधेयक लाए। एनडीए इस तरह के विधेयक पर अपना स्पष्ट समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्यथा कांग्रेस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

(ओ. पी. कोहली)
मुख्यालय प्रभारी